विचार बिन्दु

हृदय की विशालता ही उन्नति की नींव है। –जवाहरलाल नेहरु

एक देश, एक शिक्षा

प्रधानमंत्री ने आव्हान किया है कि भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष, 2047 तक भारत देश के विश्व के विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित कराना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, अब तक की यात्रा विकासशील देश के रूप में रही है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि देश की पूरी जनसंख्या, देश की प्रगति में सक्रिय और अपनी क्षमता अनुसार पूरा योगदान दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि देश के सभी बच्चों को समान रूप से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। विश्व में कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है जहां के सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध न हों। शिक्षा में जितनी असमानता हमारे देश में में है, उतनी संभवतया किसी देश में नहीं है। सर्वाधिक समृद्ध देश अमेरिका में भी लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को एक समान स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है एवं वे सभी बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। भारत में यह स्थिति ठीक उल्टी है। ठीक-ठाक शिक्षा भी केवल पांच प्रतिशत बच्चों को ही प्राप्त है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में आया और उसमें विद्यालयों के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किए गए। यह खेद का विषय है कि आर टी ई कानून लागू होने के लगभग 13 वर्ष बाद एवं स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी भारत के लगभग 15 लाख विद्यालयों में से अधिकतम एक लाख विद्यालय ही ऐसे हैं जो आईटीआई कानून में लिखी गई विभिन्न शर्तों की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रति सरकारों की उदासीनता का ही परिणाम है कि न तो भारत का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों में स्थान बना पाया एवं न ही यहां की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी असमानता भारत में है, उतनी किसी अन्य देश में नहीं है। दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करना पाठकों के लिए उपयोगी होगा।

दृश्य एक-- शहर के किसी कच्ची बस्ती अथवा गांव का राजकीय विद्यालय कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। पास में गंदे पानी का नाला बह रहा हो। आसपास, गाय भैंस, बकरियां आदि जानवर मुक्त रूप से विचरण करते हों। जहां पर दो कच्चे पक्के छोटे कमरे हों। बिजली की नियमित व्यवस्था न हो। खेल के मैदान का तो प्रश्न ही नहीं। बालिकाओं के शौचालय न हों। शिक्षक इक्का-दुक्का ही वहां पद स्थापित हों और वे भी अपनी इच्छा अनुसार कभी-कभार विद्यालय आते हों। अनुपस्थित अध्यापकों के बारे में पता करने पर बताया जाए कि वे कोई सूचना देने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय गए हैं। बच्चों के बैठने के लिए न बेंच की व्यवस्था हो न टेबल कुर्सी की। पीने का पानी नहीं हो। अधिकांश विद्यालयों में बैठने के लिए फटी हुई टाट पट्टी हो। एक-एक कमरे में दो-तीन कक्षा के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके अलग-अलग समूह में बैठा दिया गया हो, और एक ही शिक्षक सबको एक साथ पढ़ाने का उपक्रम करता हो।

इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5-7 वर्ष की तथाकथित स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी न तो सरल अंकगणितीय गणना कर सकते हैं, न ही सरल हिंदी में लिख-पढ़ या समझ सकते हैं। इसकी पुष्टि 'प्रथम' संस्थान द्वारा किए गए शिक्षा के स्तर के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Staus of Education Report) में गत कई वर्षों से हो रही है। शिक्षा को प्राथमिकता न दिए जाने का ही परिणाम है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के स्थान पर अधिकांश बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर में गिरावट ही देखी जा रही है। देश के 90 प्रतिशत बच्चे ऐसे ही विद्यालयों में पढ़ रहे हैं।

दृश्य दो-- बहुत बड़ा स्कूल परिसर है। बच्चों को स्कूल की बस या कारों के द्वारा लाया जा रहा है। हरे-भरे, लंबे-चौडे खेल के मैदान हैं। प्रत्येक क्लासरूम वातानुकूलित है, स्मार्ट बोर्ड भी है। प्रत्येक बच्चे के पास लैपटॉप है। सुसज्जित प्रयोगशाला है। सभी बच्चे साफ-सुथरी अच्छी यूनिफॉर्म में आते हैं। प्रति दस विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। पढ़ाई के अलावा कई गैर शैक्षणिक गतिविधियां समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। इन विद्यालयों के माता-पिता, बच्चों को घर पर पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

इस प्रकार के कुछ विद्यालय किसी ट्रस्ट या मिशनरी द्वारा संचालित हैं, किन्तु अधिकांश, व्यवसाय की तरह संचालित किए जाते हैं।

दृश्य 3-- गली मोहल्ले में खास पर शहरों की कच्ची बस्तियों में आजकल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं, जहां पर 1000-1500 मासिक फीस ली जाती है।

इनमें तथा-कथित रूप से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। घरों पर काम करने वाले, ड्राइवर अथवा मजदूरी करने वाले कई अभिभावकों के बच्चे इनमें पढ़ते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि निर्धन व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए वे दिन-रात कडी मेहनत करके, अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचा कर, बच्चों की फीस जुटाते हैं। इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का शोषण होता है और उन्हें 5-7000/- प्रति माह का वेतन मिलता है। ऐसे विद्यालय को चलाने वालों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को व्यवसाय की तरह ही चलाना है।

देश के शिक्षकों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस केवल स्थानांतरण के चक्कर से उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। स्थानीय, सदैव उपलब्ध शिक्षक, बच्चों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को जोड़ पाएगा बच्चों का भविष्य देश के भविष्य के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है।

दूसरी श्रेणी के विद्यालय जिनका उल्लेख ऊपर किया है, उन्हें चलाने वाले अधिकांश व्यवसायी होते हैं, जिन्होंने जिन्होंने शराब, पत्थर, परिवहन या रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय से अकूत सम्पत्ति अर्जित कर शिक्षा को भी व्यवसाय की तरह चलाना प्रारंभ किया है। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय तक उपलब्ध हैं। शिक्षा के निजीकरण का जो दौर लगभग 30 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, वह अब चरम पर है। अच्छी सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के दायित्व से सरकारों ने लगता है, मुंह मोड़ लिया है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में लगभग सारे विद्यालय सरकारी हैं। भारत में भी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हैं जो इस बात को सिद्ध करते है कि सरकार चाहे तो अच्छे विद्यालय संचालित कर सकती है।

दृश्य एक में उल्लिखित विद्यालय अमीर, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए सीमित होकर रह गए हैं। स्वाभाविक है, जो विद्यार्थी ऐसे विद्यालय से निकलेंगे, वे जीवन की हर दौड़ में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में पहले से ही कहीं आगे खड़े होंगे। उनके माता-पिता के पास पर्याप्त संसाधन होने के कारण वह उच्च शिक्षा हेतु निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने भविष्य को संवारने में लग जाएंगे। इनमें से कई तो विदेशों में जाकर बसने की सोच लेते हैं। आजकल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जो कक्षा 12वीं के बाद ही सीधे स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु प्रवेश को आसान बनाने के लिए उनके लिए आई बी का परीक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। इन विद्यालयों का वार्षिक शुल्क 3 लाख रुपए से 30 लाख तक का हो सकता है।

अपनी शिक्षा पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने के बाद, शिक्षा पूरी होते ही, उसे किस प्रकार समाज से वसूल करें, यही मुख्य ध्येय हो जाता है। ऐसा करने में, चाहे गरीब परिवारों का शोषण ही क्यों न करना पड़े? जिस प्रकार के कॉर्पोरेट अथवा निजी चिकित्सालय इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त परिवारों के बच्चों द्वारा खोले गए हैं, वे अन्य व्यवसाय की तरह ही मुनाफा कमाने के माध्यम बनकर रह गए हैं। सबको स्वास्थ्य सुलभ कराने का सपना, जनता से दूर करने में, ऐसे निजी अस्पताल संचालकों की बहुत बड़ी भूमिका है।

प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार एवं, शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सभी परिवारों के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा उपलब्ध कराए बिना संभव नहीं हो सकता है। हम 142 करोड़ व्यक्तियों का देश होने का दम भरते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कई बार अनेक स्तरों पर सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में होने को बहुत महत्त्वपूर्ण बताते हैं। यह जनसंख्या, तभी भारत को मजबूत और विकसित बनाने में योगदान कर पाएगी, जब इन सबको समान रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल तो ऐसा करना कई वर्षों तक संभव नहीं लगता क्योंकि किसी भी दल द्वारा अपने चुनाव प्रचार में अच्छी और समान शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की बात तक नहीं की जाती है। किसी भी दल के घोषणा पत्र में इस बारे में कोई उल्लेख तक नहीं होता कि वह सत्ता में आने पर सबको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित विद्यालय, पर्याप्त शिक्षकों के अभाव एवं माता-पिता के शिक्षित न होने से उनके मार्गदर्शन के अभाव में, किस प्रकार के नागरिक समाज में बड़े होकर बनेंगे, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। समाज में जिस प्रकार से अपराध और वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है उसमें और तेजी से वृद्धि होगी, यदि हम अधिकांश जनसंख्या को अच्छी शिक्षा प्रत्येक स्तर पर प्रदान नहीं कर पाएंगे।

इसका हल केवल यही है कि सरकार अगले 10 वर्ष सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इस हेतु, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराना होगा। यह कार्य केवल निजी संस्थाओं के भरोसे छोड़ देने से शिक्षा में असमानता को, सरकार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा ही देगी। असमान शिक्षा, देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। यह बात सबको अब भी समझ में नहीं आई तो फिर विकसित राष्ट्र का सपना केवल जुमला ही बनकर रह जाएगा। जब सबको समान अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब ही सब किसी उपयोगी कार्य में संलग्न हो पाएंगे। तब, बेरोजगारी की समस्या भी नहीं रहेगी। इसके लिए न केवल राज्य स्तर पर शिक्षा और विद्यार्थी के अनुपात को ठीक करना होगा अपितु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समुचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। शिक्षक-प्रशिक्षण को भी आमूल चूल रूप से बदलना होगा ताकि वे बच्चों को खोजी एवं जिज्ञासु बनने हेतु प्रोत्साहित कर सकें।

सर्वाधिक उपयुक्त तो यह होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने सार्वजनिक संबोधनों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात करना प्रारंभ करें एवं इस हेतु बजट की किसी भी प्रकार की समस्याओं को आड़े नहीं आने दें। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी जो तय कर लेते हैं, उसे कर गुजरने की क्षमता भी रखते हैं। बस केवल उन्हें अपनी इस क्षमता और शक्ति का प्रयोग देश में समान शिक्षा प्रदान करने की दिशा में करने की आवश्यकता है।

सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने हाथ में रखते हुए अन्य सभी क्षेत्रों में निजीकरण कर दे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। सरकार को कई प्रकार के व्यवसाय के कामों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह मूल रूप से शासन की जिम्मेदारी है। यही वह बात है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

आशा करनी चाहिए कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दल, शिक्षा के महत्व को समझ कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में करेंगे। शिक्षा की प्रशासनिक संरचना में भी आवश्यकता के अनुसार सारे परिवर्तन किए जाने चाहियें।

देश के शिक्षकों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस केवल स्थानांतरण के चक्कर से उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। स्थानीय, सदैव उपलब्ध शिक्षक, बच्चों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को जोड़ पाएगा बच्चों का भविष्य देश के भविष्य के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है।

आइए, हम सब मिलकर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सरकारों पर दबाव बनाएं। ऐसा करके हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने के यज्ञ में अपनी आहुति दे पाएंगे।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

नहीं थम रहे सड़क हादसे

अविनाश जोशी

सड़क हादसे जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। परिवार टूट जाते है एवम कई बार तो यह प्रश्न होता है की आगे की जिंदगी कैसे जी जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन देश के किसी भी भाग में सड़क हादसा न हो और कुछ लोगों को जान से हाथ न धोना पड़े। अमूमन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले आम जन होते हैं। इसलिए वे अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाते, जिससे उन दुर्घटनाओं पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है। अनुमानत हमारे देश में हर मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है और हर तीन मिनट में सड़क दुर्घटना में एक जान जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में ही होते हैं। जबकि चीन, रूस और अमेरिका जैसे कई देशों में भारत की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में कारें हैं। दुर्घटनाओं पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पिछले दस साल में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में लगभग चालीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में आबादी में सिर्फ बारह प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ज्यादातर मौतें दो-पहिया वाहनों की दुर्घटना में हुई हैं और तेज व लापरवाही से वाहन चलाना उनकी वजह रही है।

आज के युग में विज्ञान ने मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल बना दिया है उससे उतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता जितना पहले करना पड़ता था हर क्षेत्र में आज मनुष्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करता है वाहन भी विज्ञान की ही देन है जिसके माध्यम से आज हम एक दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं परंतु इन्हीं भावनाओं के कुछ नुकसान भी है वायु को दूषित करने के अतिरिक्त सड़क दुर्घटना भी इन्हीं वाहनों की देन है। सड़क सुरक्षा के मानकों का महत्त्व समझना और समझाना दोनों जरूरी है, क्योंकि देश में सड़क नेटवर्क का तेजी से हो रहे विस्तार, गाड़ियों की संख्या में हो रही वृद्धि और शहरीकरण का नकारात्मक पक्ष सड़क दुर्घटनाओं के रूप में सामने आ चुका है। सड़क हादसों में होने वाली मौतें और अपंगता की बढ़ती संख्या ने यह सोचने पर विवश किया है कि क्या विकास की धुरी मानी जानी वाली सड़कें मौत का प्रमुख कारण और जगह बनती जा रही हैं?

हमारी सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण के उचित कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही वाहनों की सुरक्षा के मानकों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए। भारी वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को परमिट दिए जाने की प्रक्रिया में कड़ाई बरती जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी तय की जाए, साथ ही छोटे बच्चों और किशोरों के वाहन चलाने पर कड़ाई से रोक लगे। तेज रफ्तार, सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता अभियान चलाए जाएं, तभी भारत में सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी।

शहरों में लालबत्ती पार करने, अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने और आगे निकलने की प्रवृत्ति आम है। यह दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने जैसा है। इससे सैकड़ों लोग घायल होते और मरते हैं। इसमें यातायात पुलिस की लापरवाही कम जिम्मेदार नहीं है। वहीं हादसा होने के बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में हुई देरी घायल व्यक्ति की मौत का बड़ा कारण है, मगर आम लोग घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे नहीं आते। राज्य सरकार की तरफ से घायल को तत्काल चिकित्सा और राहत पहुंचाने वाली सुविधाएं भारत में बहुत कम हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा संबंधी कई उपाय किए हैं। उनमें सुरक्षित बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करना, जागरूकता पैदा करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा सूचना का डेटाबेस तैयार करना जैसे उपाय शामिल हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मगर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने इन सारे उपायों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वजह है कि इन उपायों का पालन ठीक से नहीं कराया जा रहा है। कठोर कानून के बावजूद लोगों को उसका भय नहीं सतता, जिसका परिणाम प्रतिदिन सैकड़ों सड़क हादसों के रूप में सामने आता है। विडंबना ही कही जाएगी कि जो सुझाव सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते रहे हैं उन्हें मुस्तैदी के साथ पालन कराने के लिए यातायात पुलिस कुछ दिन तो काम करती है, लेकिन धीरे-धीरे फिर वही पुराना ढर्रा कायम हो जाता है। वरना क्या कारण है कि भारत में ही सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं?

विश्व के कुल वाहनों का महज दो फीसदी भारत में हैं, पर सड़क हादसों में होने वाली मौतें बारह फीसदी से ज्यादा हैं। दुनिया के तमाम देशों ने अपने कड़े सड़क कानून और जनजागरूकता अभियानों के जरिए सड़क हादसों में वृद्धि नहीं होने दी, लेकिन पिछले बीस सालों में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से भारत में पचहत्तर फीसद से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में कितना सड़क कानूनों का पालन किया और कराया जाता है। सड़क सुरक्षा पर जारी की गई विश्व स्थिति रिपोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामले की मुख्य पांच वजहें बताई हैं। इनमें सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, सुरक्षा पेटी न बांधना, दुपहिया चलाते वक्त हेलमेट न पहनना और बच्चों की सुरक्षा के उपायों की अनदेखी शामिल है।

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मुताबिक नब्बे फीसदी हादसे ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं। इस पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त कायदे से जांच-परख की जाती है? क्या सुरक्षा मानकों पर गाड़ियों की कड़ी जांच-पड़ताल होती है? ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर क्या और सख्ती होनी चाहिए? भारत में रोज तेरह सौ से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर दिन सड़क हादसों में करीब चार सौ मौतें होती हैं। सड़क हादसों में सालाना करीब बीस अरब डॉलर का नुकसान होता है।

भारत में बारह करोड़ से ज्यादा वाहन हैं और इनके चलने के लिए पर्याप्त सडकें होना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोका जा सकता है? जिस तरह देश-समाज की सुरक्षा वाले कानूनों का पालन महज दिखावा बन कर रह गया है वैसे ही यातायात नियमों की अनदेखी एक प्रवृत्ति बन गई है। यातायात नियमों का पालन, अतिरिक्त सावधानी, वाहन को नियंत्रित सीमा में रखना, पैदल यात्रियों का सड़क पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना, सड़कों को मानक रूप में बेहतर बनाए रखना और 'ओवरटेक' करने से बचना जरूरी है। सड़क सुरक्षा सप्ताहों में जिस तरह पुलिस यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक और बाध्य करती है, वैसी जागरूकता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो हादसों में कमी लाई जा सकती है।

–अविनाश जोशी,
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

बड़गांव व रघुनाथपुरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

विकास कार्य नहीं होने पर वार्ड पंचों ने इस्तीफे की धमकी दी

■ **सचिव को सौंपा ज्ञापन, सड़क व नाली निर्माण की मांग**

अजमेर, (कासं)। भिनाय पंचायत समिति से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम बड़गांव व रघुनाथपुरा की अच्छी खासी आबादी है। चुनाव के दिनों में नेता लोग यहां दिन भर चक्कर काटते हैं। बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन अब हालत देखें तो गांव पर तरस आता है। लेकिन न तो इस हालत को देखने के लिए नेता आते और न ही कभी कोई अफसर। विकास कार्य की कमी के चलते यह दोनों गांव पिछड़ता नजर आ रहा है। सरकार के समान विकास के वादे झूठे साबित हो रहे हैं।

ग्रामीण तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। गांव की सरकार यानि ग्राम पंचायत के कार्यकाल को भी करीब तीन साल गुजर चुके हैं। लेकिन गांव के हालात जस के तस है। वास्तव में कोई सुधार गांव में नहीं हुआ है।

ग्राम सुरखंड बड़ागांव के वार्ड 3 के पंच विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे हर समय गांव की गलियों में गंदा पानी भरा रहता है। इसके अलावा लगभग हर गली निर्माण न होने के कारण बुरा हाल है। गांव की ज्यादातर गलियां खस्ता हाल में है। हर समय कीचड़ भरा रहता है। गांव की शायद ही कोई गली ऐसी हो जिसमें कीचड़ न भरा हो। इन सबके चलते गांव की वर्तमान स्थिति बेहद खराब है। गांव की गलियों से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है।

ग्राम पंचायत के पांचों ने सोमवार को सचिव दुलाराम जांगिड़ को ज्ञापन सौंप कर अवगत करवाया कि ग्रामवासियों ने बड़गांव में विकास कार्य करवाने के लिए हमारे ऊपर विश्वास करके हमे वार्ड पंच चुना, लेकिन गांव में विकास कार्य नहीं होने कारण ग्रामवासियों के विश्वास पर हम खरे नहीं उतर पाए इसलिए आए दिन हमें ग्रामवासियों की गालियां व ताने सुन-सुन कर कान पक गए।

विगत तीन वर्षों से ना तो पक्का काम चला और न ही चलने की संभावना दिख रही है। ग्राम बड़गांव में नालियां, पुलिया व सीसी सड़क आदि की ग्राम बड़गांव में जरूरत होने के बावजूद पंचायत प्रसाशन का ध्यान होते हुए भी आंख पर पट्टी बांध कर नजर अंदाज किया जा रहा है। जबकि ग्राम पंचायत के फंड में पैसा पड़ा है। ग्राम सभा व वार्ड सभा में प्रस्ताव लिए जाते है, लेकिन काम नहीं किया जाता है। फिर ग्राम सभा व वार्ड सभा करने का क्या महत्व सरकार द्वारा गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सड़कें व नालियां टूटी हुई होने के कारण कीचड़ व गंदगी पूरे गांव में फैली हुई है। बार-बार इन विकास कार्यों के लिए पंचायत प्रसाशन को अवगत करवाने व निवेदन करने के बाद भी चक्कर पर चक्कर दिए जा रहे हैं। कुछ कार्यों की छह माह पूर्व स्वीकृति निकालने के बावजूद भी विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। प्रसाशन द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा व बड़गांव के ग्राम वासियों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड पंचों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यो पर 15 दिवस में स्वीकृति व स्वीकृत निकले हुए कार्यों पर काम नहीं चलाया गया तो हम सभी वार्ड पंच एक साथ इस्तीफा देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पंचायत प्रशासन की होगी। इस दौरान वार्ड दो पदम भील, वार्ड तीन के विष्णुदत्त शर्मा, वार्ड चार के महावीर सोनी, वार्ड पांच रामकाना मेघवंशी, वार्ड छह के लाडा देवी, वार्ड सात के धनराज जाट सहित बड़ी संख्या में वार्ड पंच उपस्थित रहे। सचिव दूलाराम जांगिड़, ग्राम पंचायत बड़गांव का कहना है कि जिन कार्यों की स्वीकृति निकाली गई है, उन कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करवा दिया जाएगा।

"वंदे भारत ट्रेन" हादसे का शिकार होने से बची

■ **बदमाशों की करतूत, यह घटना गंगरार और सोनियाणा स्टेशनों के बीच हुई**

■ **पायलेट और सहायक की नजर पत्थरों पर पड़ गई, हादसा टला**

भीलवाड़ा, (निसं)। हाईस्पीड वंदे भारत ट्रैन सोमवार सुबह बदमाशों की करतूत के चलते दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। घटना, गंगरार और सोनियाणा स्टेशनों के बीच हुई। गनीमत रही कि ट्रैन के पायलेट और सहायक की नजर पत्थरों पर पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, हाईस्पीड वंदे भारत ट्रैन सोमवार सुबह उदयपुर से रवाना होकर करीब साढ़े नौ बजे सोनियाणा-गंगरार रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक पोल 158/18-19 से कुछ दूरी पर पहुंची थी कि ट्रेन के पायलेट व सहायक की नजर ट्रैक पर रखे पत्थरों व ट्रैक के बीच गढ़े कीलों पर पड़ गई। चालक ने सतर्कता बरतते हुये ट्रेन को ब्रेक लगाकर इन पत्थरों व कीलों से 5-7 मीटर की दूरी पर रोक लिया। इससे यह ट्रैन दुर्घटनाठास्त होने से बच गई। यहां दोनों ट्रैक पर करीब दस मीटर की दूरी तक गिट्टी पत्थर रखे हुये मिले और दो कीलें दोनों पटरियों के बीच गढ़े हुये थे। पायलेट व सहायक ने इंजिन से उतर कर ट्रैक से पत्थर व कीले हटाये और इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल को दी। करीब 10 मिनिट खड़ी रहने के बाद वंदे भारत ट्रेन भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी व रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु की है।

रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी व रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरु की।

राशिफल मंगलवार 3 अक्टूम्बर, 2023

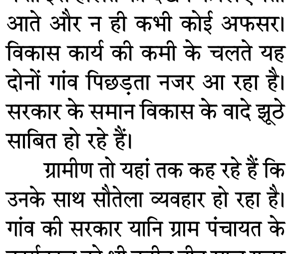

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, कृत्तिका नक्षत्र सांय 6:04 तक, वज्र योग प्रातः 8:17 तक, कौलव करण सांय 5:52 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कन्या, बुध-कन्या, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सांय 6:04 तक है। कुमार योग सांय 6:04 से आरम्भ होगा। आज मंगल तुला राशि में सांय 5:58 पर प्रवेश करेगा। आज कृत्तिका ओर पंचमी का श्राद्ध है। आज ईद-ए-मौलाद है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 1:44 तक, शुभ 3:12 से 4:40 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:08

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-परिवार के कारणों के कारण भागदौड़ रहेगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर
घर-परिवार में अनावश्यक वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। अनावश्यक धन खर्च होगा। परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। व्यावसायिक अड़चनें अभी बनी रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक परेशानियों से राहत मिलेगी।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।